

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी ।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा में श्रीमान महानिबन्धक महोदय
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश
बलरामपुर ।

विषय : प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020- 2021 दिनांकित 22. 12. 2021 को निरस्त
(Expunge) कर उचित प्रविष्टि दिये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन ।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वर्ष 2020- 2021 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि कोविड- 19 के कारण माह जुलाई 2021 तक दी जानी थी लेकिन मुझ न्यायिक अधिकारी को यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अत्यधिक विलम्ब से दिनांक 22. 12. 2021 को दी गयी, और यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मुझ न्यायिक अधिकारी को कभी भी संसूचित नहीं की गयी । यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि मुझ न्यायिक अधिकारी के पोर्टल पर अपलोड की गयी थी । मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा उक्त पोर्टल को कई बार खोला गया लेकिन उक्त पोर्टल कभी भी मुझ न्यायिक अधिकारी से नहीं खुला । मैंने अपने आशुलिपिक से भी उक्त पोर्टल को कई बार खुलवाया लेकिन उक्त पोर्टल आशुलिपिक भी नहीं खोल पाये, इस कारण उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की कभी जानकारी ही नहीं हो सकी । जैसे ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की मुझ न्यायिक अधिकारी को जानकारी हुई कि तब तक मुझ न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण जनपद झाँसी से जनपद बलरामपुर हो गया । जनपद बलरामपुर में कार्यभार ग्रहण करने व झाँसी के सरकारी आवास को रिक्त करने के उपरान्त तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार Action Plan 2022- 2023 के तहत सभी पत्रावलियों को छँटवाने, व्यवस्थित करवाने व अपलोड करवाने में व्यस्त होने के कारण उक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है । यदि उक्त वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की जानकारी प्रारम्भ में ही हो जाती तो निश्चित रूप से मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर दिया जाता । इस प्रकार प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, वह उपरोक्त कारणों से हुआ है । माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है, उसे क्षमा करते हुए प्रत्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा करें ।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020- 2021



दिनांकित 22. 12. 2021 को निरस्त (Expunge) करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार निम्नवत है:-

1. महोदय सादर ससम्मान निवेदन करना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी ने जनपद झाँसी में दिनांक 26. 09. 2019 को लघुवाद न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और दिनांक 04. 07. 2022 को कार्यभार छोड़ा और इस दौरान कभी भी किसी पक्षकार/ अधिवक्ता ने कभी भी मेरी कोई शिकायत नहीं की। इस दौरान जनपद झाँसी में श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव व श्री अविनाश कुमार सकसैना भी जनपद न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे लेकिन उनके कार्यकाल में कभी कोई शिकायत नहीं हुई। यहाँ तक कि दिनांक 26. 10. 2021 से पूर्व भी कभी किसी पक्षकार / अधिवक्ता ने मुझ न्यायिक अधिकारी की कोई शिकायत नहीं की, और किसी भी न्यायिक अधिकारी ने मेरी कभी भी कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। दिनांक 26. 10. 2021 को जो तथाकथित फर्जी शिकायत जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के नाम से हुई है, वह फर्जी शिकायत स्वयं श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी द्वारा जनपद झाँसी के टॉप - टेन अपराधी, अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ला, श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट, श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट आदि के माध्यम से मुझ न्यायिक अधिकारी पर अनुचित दबाव बनाने के लिए करायी गयी थी। श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी, मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति सदैव ही वैमनस्य व विद्वेष का भाव रखती रही थी। उन्होंने मुझ न्यायिक अधिकारी को अपने कार्य - काल के दौरान सदैव ही मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उनके द्वारा प्रेषित अनेको अर्द्ध शासकीय पत्रांक हैं, लेकिन मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा अपने कार्यों के प्रति सदैव ही ईमानदारी व सत्य निष्ठा से कार्य किया गया। मुझ प्रार्थी द्वारा जनपद झाँसी में कार्यभार ग्रहण किये जाने के समय से कार्यभार छोड़ने के समय तक सदैव निष्पक्ष तरीके से गुण- दोष के आधार पर कार्य किया गया। मुझ न्यायिक अधिकारी की जो भी फर्जी शिकायतें हुई हैं, वे समस्त शिकायतें श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी के कहने पर श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, श्री रमेश यादव एडवोकेट, श्री सुनील शुक्ला एडवोकेट और माह फरवरी 2022 में श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) झाँसी को संरक्षण दिये जाने, उनको उकसाने, बहलाने व फुसलाने पर उनके द्वारा की गयी है। दिनांक 22. 02. 2022 से दिनांक 24. 02. 2022 तक श्रीमान जनपद न्यायाधीश की सलाह पर उक्त अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में शामियाना (टेन्ट) व माईक लगाकर न्यायालय कार्यावधि के दौरान धरना- प्रदर्शन व शोर- शराबा कारित किया लेकिन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने उस धरना- प्रदर्शन व शोर- शराबा को बन्द नहीं करवाया जबकि उक्त अवधि में धारा 144 दं०प्र०सं० व चुनाव आचार संहिता लागू थी। मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में श्रीमान जनपद न्यायाधीश को दिनांक 22. 02. 2022 को पत्र प्रेषित किया गया लेकिन उनके द्वारा कोई कार्यवाही इस बावत नहीं की गयी। दिनांक 24. 02. 2022 को पुनः उक्त अधिवक्ताओं के शोर - शराबा कारित किये जाने पर मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा इस तथ्य का आदेश पत्र पर उल्लेख किया गया और इस तथ्य की सूचना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को प्रेषित की गयी तत्पश्चात उक्त धरना - प्रदर्शन समाप्त हुआ, इस सम्बन्ध में समस्त

उल्लेख संलग्नक सं० 11 . (xiii) (a) लगायत 11. (xiii) (g) में किया गया है। विशेष रूप से उल्लेख करना है कि माह अप्रैल 2022 के पश्चात से पुनः किसी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं हुई और श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी के दिनोंक 31. 05. 2022 को सेवानिवृत्त होने के पश्चात से मुझ प्रार्थी के कार्यभार छोड़ने की तिथि 04. 07. 2022 तक भी कोई शिकायत नहीं हुई।

2. श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मुझ न्यायिक अधिकारी के जिन कार्यों के प्रति सराहना करते हुए जो सकारात्मक टिप्पणी की है , उससे यह ज्ञात होता है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा सत्य निष्ठा व ईमानदारी से कार्य किया गया है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया द्वारा मुझ न्यायिक अधिकारी के कार्यों के प्रति की गयी सराहना , जो उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया है , के कुछ दृष्टान्त निम्नवत हैं:-

01. (a) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (c) में स्वयं श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह स्वीकार किया है कि

01 (c) .	If he is cool minded and does not lose temper in court.	Yes
-----------	---	-----

01. (b) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (e) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01. (e) . Control over the files in the matter of:

01. (e) (i) (a) .	Proper fixation of cause list:	Yes
01. (e) (i) (b) .	Whether sufficient number of cases are fixed by him to keep him engaged during full court hours?	Yes
01. (e) (ii) .	Avoidance of unnecessary adjournments:	Unnecessary adjournments have been avoided.

01. (c) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (f) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01 (f) .	Whether Judgement on facts and on law are on the whole sound, well- reasoned and expressed in good language?:	Yes
-----------	---	-----

Note:- The following factors should also be indicated in filling up this column:

01 (f) (i) .	Marshalling of facts;	Proper
01 (f) (ii) .	Appreciation of evidences;	Proper
01 (f) (iii) .	Application of law.	Proper

01 (g) (ii) .	Number of cases decided wherein all witnesses of fact turned hostile and the case ended in acquittal.	Nil
-----------------	---	-----



01. (d) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (g) (iv) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01. (g) (iv).	Number of cases wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered.	NIL
01 (h).	Control over the Office and Administrative capacity and tact:	Control over his own office Effective.

01. (e) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (I) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01 (I).	His punctuality and regularity in sitting on the dais in court during court hours?	Punctual
---------	--	----------

01. (f) यह कि वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा 01 (n) में स्वयं यह स्वीकार किया है कि

01 (n).	Behaviour towards women (respect and sensitivity exhibited towards them)	No woman made any complaint
---------	--	-----------------------------

3. (i) माननीय महोदय यह अत्यन्त ही विचारणीय एवं सुसंगत प्रश्न है कि जिस न्यायिक अधिकारी के सम्बन्ध में स्वयं श्रीमान जनपद न्यायाधीश उपरोक्तानुसार आंकलन कर रही हैं वह न्यायिक अधिकारी किस प्रकार से गलत हो सकता है। श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय की उपरोक्त टिप्पणी यह दर्शाती है कि मुझ न्यायिक अधिकारी समय से व नियमित रूप से कोर्ट में डायस पर बैठता रहा है, वह शान्त प्रवृत्ति का है। Cause list Proper तरीके से fix की जाती है। During full court hours स्वयं को engaged रखने के लिए, उसके द्वारा sufficient number of cases fix किए गये। उसके द्वारा Unnecessary adjournments have been avoided. Judgment on facts and on law are on the whole sound, well- reasoned and expressed in good language. Marshalling of fact, Appreciation of evidences and Application of law is Proper. In none case wherein after conclusion of arguments and reserving them for judgment, rehearing was ordered. Control over his office and administrative capacity and tact is effective. He is punctual as well as regular in sitting on the dais in court. Behaviour towards women (respect and sensitivity, No woman made any complaint.

(ii) उपरोक्त टिप्पणियाँ यह दर्शाती हैं कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा न्यायालय में जो भी कार्य किया गया वह उचित तरीके से किया गया उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसके बावजूद Remark में मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity को जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत withhold किया गया और यह अंकित किया गया "kindly see remark column" लेकिन यह नहीं दर्शाया गया कि इस बावत

कौन सा 'remark column' है और कौन सा संलग्नक है।

(iii) ठीक इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि he is not fair and impartial in dealing with the public and bar, "kindly see remark column" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत अंकित की गयी है और इसमें भी नहीं दर्शाया गया है कि इस बावत कौन सा 'remark column' है और कौन सा संलग्नक है।

(iv) ठीक इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि "litigants and members of bar do not entertain good opinion about him in general" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत अंकित की गयी है जबकि पक्षकार व बार के अधिवक्तागण मेरे न्यायालय में अधिकांशतः कार्य करते थे, और सबसे अधिक साक्ष्य मेरे न्यायालय में ही अंकित हुआ। यदि पक्षकार या अधिवक्तागणों की, मेरे बारे में अच्छी राय नहीं होती तो मेरे न्यायालय में इतना अधिक कार्य नहीं होता। उदाहरण स्वरूप जनपद झाँसी में माह सितम्बर 2021, माह अक्टूबर 2021 में मेरे न्यायालय में जो कार्य हुआ, इस सम्बन्ध में श्री मृदुत कांत श्रीवास्तव जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जारी सूची की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

[संलग्नक सं० 01 व 03]

(v) इसी प्रकार Remarks में यह अंकित करना कि "however for other administrative assignments kindly see remark column" यह प्रविष्टि भी जानबूझकर, वैमनस्य व विद्वेष के भाव के तहत अंकित की गयी है। जिस सम्बन्ध में यह प्रविष्टि अंकित की गयी है और जो संलग्नक सं० 04 व 07 के रूप में संलग्न किया गया है और जो अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 07/ 2021 दिनांक 01. 07. 2021 जारी किया गया है उसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त पत्रांक कभी भी मेरे न्यायालय में प्राप्त ही नहीं कराया गया जिसका उल्लेख मेरे द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांकित 15. 07. 2021 मय संलग्नक (पेशकार की आख्या) में किया गया है, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्नक सं० 07 में दर्शाया गया है)।

(vi) श्रीमान जनपद न्यायाधीश को, उक्त कार्य के निष्पादन हेतु, पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र भी प्रेषित किये गये। उपलब्ध कर्मचारी द्वारा संतोषजनक तरीके से कार्य नहीं किया गया जिसकी सूचना समय-समय पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को मेरे द्वारा दी गयी लेकिन उपलब्ध कर्मचारियों के कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुझ न्यायिक अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्रों के बावजूद मुझे उक्त कार्य के निष्पादन हेतु अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध न कराना व उपलब्ध कर्मचारियों के लापरवाही व दोषपूर्ण कार्यों के बावत उनके विरुद्ध कार्यवाही न करना, इससे प्रतीत होता है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति किस तरीके से विद्वेष व वैमनस्य का भाव रखती थीं।

[संलग्नक सं० 02 (a) एवं 02 (b)]

(vii) जहाँ तक Relation with members of bar (mention incident, if any), के बावत अंकित किया है कि "kindly see remark column" लेकिन यह नहीं दर्शाया गया कि इस बावत

कौन सा 'remark column' है।

(viii) महोदय इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री उदय राजपूत, अध्यक्ष व श्री छोटे लाल वर्मा, सचिव (जिला अधिवक्ता संघ झाँसी) हैं, और उनके द्वारा बार के अध्यक्ष व सचिव की हैसियत से मुझ न्यायिक अधिकारी की कभी कोई शिकायत नहीं की गयी।

[संलग्नक सं० 03]

श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, शिकायत के बावत जो भी संलग्नक बताये गये हैं, वह सभी शिकायतें असत्य व निराधार हैं जिसका उल्लेख मुझ प्रार्थी द्वारा पैरा 01 में किया गया है।

4. (i) महोदय यह भी सादर अनुरोध करना है कि दिनांक 26.10.2021 को (समस्त अधिवक्तागण) जिला अधिवक्ता संघ के नाम से की गयी शिकायत पूर्णतया फर्जी है। यह शिकायत चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व उसके साथी एवं अपराधी अधिवक्ताओं ने श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश के कहने, उकसाने व प्रोत्साहन देने पर ही की है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त शिकायत जिला अधिवक्ता संघ झाँसी के पैड पर नहीं है। यह भी अवगत करना है कि जिन अधिवक्ताओं के नाम इस शिकायत में लिखे गये हैं, उनमें से अधिकांश अधिवक्ताओं ने कोई शिकायत कभी भी नहीं की, और अधिकांशतः अधिवक्ता न तो कभी मेरे न्यायालय में आये और न ही मुझे जानते व पहचानते हैं, इसलिए उनके द्वारा शिकायत करने का कोई भी प्रश्न ही नहीं उठता है।

[संलग्नक सं० 03 व 04(a)]

(ii) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपनी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मुझ न्यायिक अधिकारी के जिन कार्यों के प्रति जो नकारात्मक टिप्पणी की है, वह टिप्पणी मुझ न्यायिक अधिकारी के प्रति विद्वेष, वैमनस्य व असदभाविक दृष्टिकोण रखते हुए मुझे तंग, हैरान व परेशान करने के लिए की गयी है और उनके सम्बन्ध में जो भी दस्तावेज संलग्न किये गये हैं, वे सुसंगत दस्तावेज नहीं हैं। जो भी शिकायतें संलग्नक के रूप में दर्शायी गयी हैं, वे समस्त शिकायतें श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया के कहने पर ही हुई हैं, उनमें से एक भी शिकायत न तो बार के अध्यक्ष और न ही सचिव द्वारा की गयी है, और न ही उनके द्वारा अग्रसारित की गयी है। अधिकांशतः शिकायतें 1. श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट, 2. श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट व 3. श्री संतोष कुमार दोहरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के माध्यम से करवायी गयी हैं।

[संलग्नक सं० 04 (a)]

(iii) महोदय यह भी अवगत कराना है कि माह सितम्बर, 2019 से माह जुलाई 2021 तक श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट बार के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कभी कोई शिकायत नहीं की गयी, इसीलिए श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने उनके इस बावत किसी भी शिकायती प्रार्थनापत्र को संलग्न के रूप में नहीं दर्शाया है।

(iv) यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि मेरे न्यायालय में विचाराधीन कुछ पत्रावलियाँ जिनमें श्री रमेश कुमार यादव, अभियुक्तगणों के अधिवक्ता थे, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने उन्हें, मेरी, झूठी शिकायत के एवज में उन्हें खुश करने के लिए, मेरे न्यायालय में विचाराधीन कुछ पत्रावलियाँ जिनमें S. T. No. 09/2018 राज्य बनाम करन सिंह एवं अन्य (बहस में नियत), S. T. No. 380/11 राज्य



बनाम संतोष एवं अन्य (सफाई साक्ष्य में नियत) व S. T. No. 30/ 2010 राज्य बनाम दुर्गा प्रसाद एवं अन्य (सफाई साक्ष्य में नियत), उनके कहे न्यायालय में दिनांक 18. 11. 2021 को स्थानांतरित भी किया।

[संलग्नक सं० 04 (b)]

5. (a) श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट के माध्यम से करवायी गयीं फर्जी व झूठी शिकायतें।

[संलग्नक सं० 05 (a)]

(b) उक्त शिकायत के बावत प्राप्त सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रतियाँ, जिनका उल्लेख अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2021 पेज सं० 08 संलग्नक सं० 2/ 4 लगायत 2/ 9 में किया गया है।

[संलग्नक सं० 05b]

(c) श्री रमेश कुमार यादव एडवोकेट द्वारा शिकायतकर्ता संजय कुमार यादव के माध्यम से करवायी गयीं फर्जी व झूठी शिकायत, दिनांक 14. 06. 2021 को जमानत प्रार्थनापत्रों पर पारित आदेश व आदेश पत्र दिनांक 14. 06. 2021 की सत्यप्रतिलिपि, जिनका उल्लेख अवमानना प्रार्थनापत्र दिनांकित 05. 05. 2021 पेज सं० 10 में अन्तिम पंक्ति व संलग्नक सं० 2/ 13 लगायत 2/ 18 में है, में किया गया है।

[संलग्नक सं० 05c]

(d) शिकायतकर्ता संजय कुमार यादव के द्वारा कोई नवीन शिकायती प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया, उसके बावजूद मुझ प्रार्थी को जानबूझकर हैरान परेशान करने के लिए अर्द्ध शासकीय पत्रांक 20/ CAO दिनांकित 27. 10. 2021 स्वतः जारी किया गया जिसके सम्बन्ध में मुझ प्रार्थी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी।

[संलग्नक सं० 05d]

6. (a) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के माध्यम से करवायी गयीं फर्जी व झूठी शिकायतें व प्रस्तुत आख्यायें।

[संलग्नक सं० 06 (a) (i) व 06 (a) (ii)]

(b) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एवं उसके मैली मददगार श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया गया एक किता जुड़वा सम्मन के बावत जन सूचना अधिकार के तहत दिये गये आवेदनपत्र एवं प्राप्त आख्या व एक किता जुड़वा सम्मन की प्रमाणित प्रति।

[संलग्नक सं० 06b]

(c) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट एवं उसके मैली मददगार श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से तैयार किया गया एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को जो शिकायत दिनांक 02. 12. 2021 को की गयी और जो स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र दिनांक 16. 12. 2021 को प्रस्तुत किया गया, वह सम्मन दिनांक 23. 12. 2021 को तामील हुआ था, अर्थात् सम्मन दिनांक 23. 12. 2021 को तामील हुआ जबकि शिकायती प्रार्थनापत्र दिनांकित 02. 12. 2021 व स्थानांतरण प्रार्थनापत्र दि० 16. 12. 2021, सम्मन तामील होने के पूर्व ही प्रेषित किया गया था।

नोट: यह तामील शुदा सम्मन एक प्रति में है, जबकि शिकायत एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर की गयी थी

जिसके एक भाग पर सफ़ेदा लगा हुआ है जबकि तामील शुदा सम्मन में सम्बन्धित लिपिक द्वारा checked by me अंकित है, इस सम्मन में SHO ने दिनांक 01. 12. 2021 को यह सम्मन IC/ OP जेल को तामील करने हेतु निर्देशित किया है, और शिकायती एक किता जुड़वा सम्मन में यह कहीं अंकित नहीं है।

[संलग्नक सं० 06 c]

(d) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा फर्जी तरीके से बनाये गये एक किता जुड़वा सम्मन के बावत सम्बन्धित लिपिक की आख्या।

[संलग्नक सं० 06 d]

(e) श्री चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट का आपराधिक इतिहास।

[संलग्नक सं० 06 e]

07. श्री संतोष कुमार दोहरे एडवोकेट व उसके अपने अन्य मैली- मददगार अधिवक्ताओं से करवायी गयी तथाकथित फर्जी व झूठी शिकायतें।

[संलग्नक सं० 07]

08. महोदय, संलग्नक सं० 01 में वर्णित व संलग्न छायाप्रति हुसैन खाँ के प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती फरीदा बेगम ने न्यायालय के समक्ष गलत व अवैध दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिन्हें मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था लेकिन जनपद न्यायाधीश महोदया ने बिना पत्रावली, अवैध दस्तावेज व मेरी आख्या का अवलोकन किये उक्त पत्रावली को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) के न्यायालय में स्थानारित कर दिया। यहाँ यह भी अवगत करना है कि उक्त श्रीमती फरीदा बेगम ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) के न्यायालय में उस जमानतदार व दस्तावेज को प्रस्तुत ही नहीं किया जिसके बावत मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा उन्हे नोटिस प्रेषित किया गया था। श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने उक्त पत्रावली को स्थानांतरित करके, न्यायालय के समक्ष अवैध दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली जमानतदार के विरुद्ध कार्यवाही करने से बचाने का प्रयास किया। उक्त जमानतदार ने न्यायालय विशेष न्यायाधीश(डकैती) के न्यायालय में वह दस्तावेज पुनः प्रस्तुत ही नहीं किया जिस आधार पर उसने, मेरे विरुद्ध शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था।

[संलग्नक सं० 08]

09. महोदय, संलग्नक सं० 05 व 06 में वर्णित व संलग्न दस्तावेजों के बावत अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने मुझ न्यायिक अधिकारी व मेरे न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण को जानबूझकर संलग्न नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक जाँच सं० 19/ 21 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण सं० 154/ 2018 राज्य बनाम भज्जू उर्फ भजन लाल में श्री मनोज दीक्षित लिपिक को प्रेषित नोटिस संलग्न ही नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2019- 2020 को भी जानबूझकर संलग्न नहीं किया गया है जिसमें तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा



मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity - Beyond Doubt, Relation with members of bar-Cordial, Behavior in relation to brother officers- Good बताया है। [संलग्नक सं० 09]

उल्लेखनीय है कि ज्यादातर वही अधिकारी वर्तमान समय तक पदस्थ रहे जो वर्ष 2019-2020 में तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश श्री अविनाश सक्सैना महोदय के कार्यकाल में पदस्थ रहे थे।

10. संलग्नक सं० 08 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि Self Assessment Upload होने के लगभग साढ़े सात (7- 1/ 2) माह के पश्चात प्रशासनिक लिपिक द्वारा जानबूझकर गलत आख्या (श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कहने पर) लगायी गयी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि Self Assessment तैयार करते समय सभी कमियों को पूरा कर लिया गया था, प्रशासनिक लिपिक द्वारा अंकित टिप्पणी असंगत है। प्रशासनिक लिपिक से जिस प्रकार से मेरे Self Assessment पर टिप्पणी अंकित करवायी गयी, संभवतया अन्य किसी भी न्यायिक अधिकारी के Self Assessment पर इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी अंकित नहीं हुई।

नोट: (1.) मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 29. 04. 2021 को Self Assessment कम्प्यूटर अनुभाग में upload कराने हेतु प्रेषित कर दिया था और श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा यह वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दिनांक 22. 12. 2021 को दी गयी, अर्थात् Self Assessment Upload होने के लगभग साढ़े सात (7- 1/ 2) माह के पश्चात प्रशासनिक लिपिक द्वारा जानबूझकर गलत आख्या (श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कहने पर) लगायी गयी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा अवगत कराया गया था कि Self Assessment तैयार करते समय सभी कमियों को पूरा कर लिया गया था, प्रशासनिक लिपिक द्वारा अंकित टिप्पणी असंगत है। [संलग्नक सं० 10]

(2.) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने द्वारा दी गयी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020- 2021 जो दिनांक 01. 04. 2020 से दिनांक 31. 03. 2021 के लिए दी गयी है, उसमें किसी भी ऐसी घटना को नहीं दर्शाया है जिसमें मुझ न्यायिक अधिकारी की किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की कोई शिकायत की हो। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020- 2021 में जो भी नकारात्मक टिप्पणी मुझ न्यायिक अधिकारी के लिए की गयी हैं और जो संलग्नक, संलग्न किये गये हैं उनमें कोई भी शिकायत दिनांक 01. 04. 2020 से दिनांक 31. 03. 2021 के बीच की अवधि की नहीं है, और जो भी संलग्नक, संलग्न किये गये हैं, वे दिनांक 31. 03. 2021 की अवधि के पश्चात के हैं।

(3.) जहाँ तक संलग्नक सं० 04 का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त आकस्मिक निरीक्षण कभी भी मेरे न्यायालय में पेशकार को प्राप्त नहीं कराया गया और न ही वह सम्बन्धित गार्ड



फाईल में चरुपा है। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को अपने पत्र द्वारा सूचना मय पेशकार की आख्या के प्रेषित की गयी लेकिन किसी भी दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका उल्लेख पैरा सं० 03 (vi) में किया गया है।

11. (a) श्रीमती ज्योत्सना शर्मा तत्कालीन जनपद न्यायाधीश झाँसी द्वारा वर्ष 2021-2022 में प्रेषित अर्द्ध शासकीय पत्रांक व सन्दर्भ। **[संलग्नक सं० 11. (i) एवं 11. (ii)]**

(b) कर्मचारियों द्वारा कॉज लिस्ट समय से तैयार न करने, पत्रावलियाँ समय से न्यायालय में प्रस्तुत न करने पर श्रीमान जनपद न्यायाधीश को शिकायतें प्रेषित की गयीं, लेकिन किसी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी। **[संलग्नक सं० 11. (iii) to 11. (viii)]**

(c) मुझ न्यायिक अधिकारी ने सरकारी आवास पर लगे टेलीफोन कनेक्शन आदि तथा सरकारी सम्पत्ति (पानी के टैंक व पाईप लाईन) को क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना प्रेषित की, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी, और न ही अपने कार्यकाल में पानी के टैंक को बदलवाया गया और आवास रिक्त होने पर भी (मेरा आपरेशन होने के बावजूद) मुझे आवास आवंटित नहीं किया गया। **[संलग्नक सं० 11. (ix)]**

(d) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा जिन न्यायिक अधिकारियों को उत्तम / उति उत्तम प्रविष्टि दी गयी, उन न्यायिक अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध संस्थित फौजदारी निगरानी में पारित आदेश। **[संलग्नक सं० 11. (x)]**

(e) श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा, मुझ न्यायिक अधिकारी की Integrity को not beyond doubt और मेरे कार्य को is not fair and impartial in dealing with the public and bar बताया गया, इस सम्बन्ध में मुझ न्यायिक अधिकारी के द्वारा सत्र परीक्षण सं० 95/ 2018 राज्य बनाम प्रकाश कुशवाहा एवं अन्य के विरुद्ध संस्थित फौजदारी निगरानी सं० 2193/ 2021 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11. 10. 2021. **[संलग्नक सं० 11. (xi)]**

(f) श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने प्रविष्टि में जो यह टिप्पणी की है कि "He is not fair and impartial in dealing with bar" और जो संलग्नक बतायें हैं, उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि मैं, न्यायिक अधिकारी किस प्रकार से fair and impartial in dealing with bar नहीं हूँ और मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा कौन सा आदेश विधिविरुद्ध तरीके से पारित किया गया है।



महोदय, यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा जो भी आदेश पारित किये हैं, उनमें से कोई भी आदेश श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा संलग्न नहीं किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया यह ज्ञात हो सके कि मेरे द्वारा कौन- कौन से आदेश विधि विरुद्ध तरीके से पारित किये गये हैं।

[संलग्नक सं० 11. (xii)]

(g) मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 05. 05. 2022 को प्रेषित अवमानना प्रार्थनापत्र को, श्रीमान जनपद न्यायाधीश के कहने पर श्री जानकी प्रसाद CAO ने प्राप्त नहीं किया और न ही श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने अग्रसारित किया, मेरे द्वारा दिनांक 06. 05. 2022, 09. 05. 2022 व 11. 05. 2022 को स्मृतिपत्र प्रेषित किये जाने पर Back date अर्थात दिनांक 12. 05. 2022 में दिनांक 09. 05. 2022 की तिथि अंकित कर अग्रसारित किया जो मेरे न्यायालय में दिनांक 12. 05. 2022 को समय 13:30 बजे पेशकार को प्राप्त कराया गया जबकि न्यायालय का कार्यकाल समाप्त हो चुका था जिसे पेशकार ने मेरे समक्ष दिनांक 13. 05. 2022 को प्रस्तुत किया तब मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा दिनांक 13. 05. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश को इस बावत पुनः पत्र प्रेषित किया गया।

[संलग्नक सं० 11. (xiii) (a), (b), (c), (d), (e), (f) & (g)]

12. अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट के द्वारा फर्जी तरीके से एक किता जुड़वा सम्मन को तामील हुए बिना शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जबकि यह सम्मन अभियुक्त पर दिनांक 23. 12. 2021 को तामील हुआ जिसकी एक तामील शुदा प्रति की सत्यप्रतिलिपि संलग्न की गयी है, अभियुक्त के द्वारा बिना सम्मन तामील हुए एक किता जुड़वा सम्मन के आधार पर झूठी शिकायत करने पर मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश को, अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आवेदनपत्र दिनांक 30. 03. 2021 को प्रस्तुत किया गया लेकिन जनपद न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त को बचाते हुए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

[संलग्नक सं० 12]

(a) अभियुक्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट व संतोष कुमार दोहरे के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट।

[संलग्नक सं० 12. (a)]

(b) मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांकित 30. 03. 2021 के बावत श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा गलत तरीके से जारी पत्र व अर्द्ध शासकीय पत्रांक व मेरे द्वारा प्रेषित आख्या।

[संलग्नक सं० 12. (b)]

(c) शिकायतकर्ता श्री संजय यादव के द्वारा कोई नवीन शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये बिना श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा स्वतः अर्द्ध शासकीय पत्रांक जारी किया गया एवं प्रस्तुत आख्या।

[संलग्नक सं० 12. (c)]

13. दिनांक 22. 02. 2022 से दिनांक 24. 02. 2022 तक जो भी धरना- प्रदर्शन हुआ वह बार के अध्यक्ष व सचिव द्वारा आयोजित नहीं था।

[संलग्नक सं० 13]

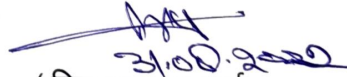


14. (a) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया ने अपने सेवानिवृत्ति के पूर्व प्रत्येक न्यायिक अधिकारी से मु० 6,000- 6,000 रूपये वसूल करवाये जिसमें मुझ न्यायिक अधिकारी द्वारा मु० 500. 00 रूपये दिये गये ।
[संलग्नक सं० 14 (a)]
- (b) इस एकत्रित धनराशि में से मु० 10,500 रूपये CJM झाँसी को, श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया की साड़ी क्रय करने हेतु दिये गये ।
[संलग्नक सं० 14 (b)]

15. मुझ न्यायिक अधिकारी के कार्य व आचरण के बावत तत्कालीन श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 20. 12. 2019 ।
[संलग्नक सं० 15]

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष रखे जाने की कृपा करें तथा माननीय न्यायालय से करबद्ध निवेदन है कि प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है , उस विलम्ब को माफ करते हुए, मुझ प्रार्थी के प्रत्यावेदन में वर्णित आधारों व संलग्न, संलग्नकों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा वर्ष 2020- 2021 में दी गयी प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि दिनांकित 22. 12. 2021 जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, को निरस्त (Expunge) कर उचित प्रविष्टि दिये जाने की महती कृपा करने की कृपा करें । प्रार्थी माननीय न्यायालय का सदैव आभारी रहेगा ।

भवदीय



(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(F. T. C. - IInd) बलरामपुर ।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 31. 08. 2022